

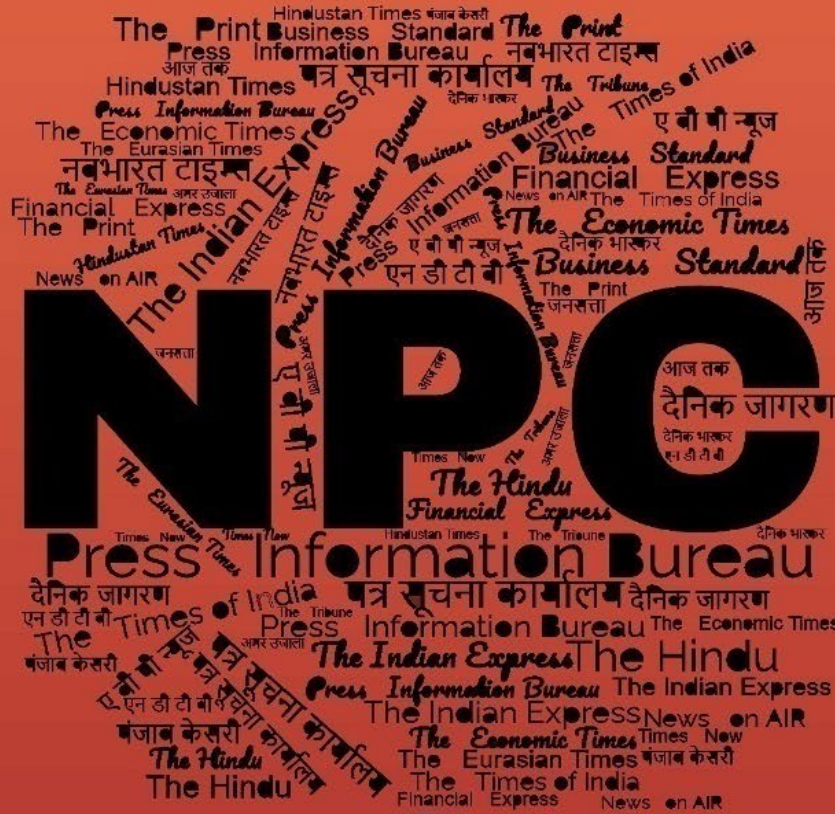
July
2024

खंड/Vol. : 49 अंक/Issue : 127
10/07/2024

समाचार पत्रों से चयित अंश Newspapers Clippings

डीआरडीओ समुदाय को डीआरडीओ प्रौद्योगिकियों, रक्षा प्रौद्योगिकियों, रक्षा नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नूतन जानकारी से अवगत कराने हेतु दैनिक सेवा

A Daily service to keep DRDO Fraternity abreast with DRDO Technologies, Defence Technologies, Defence Policies, International Relations and Science & Technology



रक्षा विज्ञान पुस्तकालय
Defence Science Library
रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केंद्र
Defence Scientific Information & Documentation Centre
मेटकॉफ हाउस, दिल्ली - 110 054
Metcalf House, Delhi - 110 054

रूसी सेना में गलत तरीके से भर्ती किए गए भारतीय लौटेंगे

पीएम मोदी ने रात्रि भोज में उठाया मुद्दा तो रूसी राष्ट्रपति ने भरी हामी, वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 100 अरब करने का रखा लक्ष्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: रूस की सेना में गलत सूचना देकर भर्ती किए गए सभी भारतीयों को स्वदेश लौटाने की इजाजत दी जाएगी। रूस की सेना में तकरीबन 40 ऐसे भारतीयों के फंसे होने की सूचना है जिन्हें रोजगार देने के बहाने बुलाया गया था और बाद में यूक्रेन सीमा पर चल रहे युद्ध में तैनात कर दिया गया। यूक्रेन के साथ युद्ध करते हुए अब तक दो भारतीय मारे भी जा चुके हैं।

रूस की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से दिए गए रात्रि भोज के दौरान मुलाकात में इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती से उठाया था और हर भारतीय को छोड़े जाने की मांग की थी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी हामी भरी है। इसके पहले पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। मोदी और पुतिन की अध्यक्षता में 22वां भारत-रूस शिखर सम्मेलन मंगलवार को संपन्न हुआ जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के कई आयामों पर बात की।

मोदी व पुतिन के बीच हुई वार्ता में भारत और रूस के रिश्तों के आयाम बदलने के भी संकेत हैं। अब दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में संबंध प्राथमिकता में नीचे आ गए हैं। वैसे मोदी ने इस बैठक में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के सैन्य क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली रूसी सैन्य सामग्रियों के कल-पुर्जे व गोला-बारूद की कमी का मुद्दा उठाया है। दोनों नेताओं की वार्ता में सैन्य सहयोग से ज्यादा आर्थिक, कारोबार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई है।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि सम्मेलन में आर्थिक एजेंडा ज्यादा हावी रहा है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को मौजूदा 65 अरब डालर से बढ़ाकर 100 डालर करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021 में 21वें शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय कारोबार को वर्ष 2025 तक



मास्को में मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी • एपी

भारत को दौरे से क्या मिला

- व्यापार, जलवायु परिवर्तन और शोध जैसे क्षेत्रों में नौ समझौतों पर हस्ताक्षर
- रूसी रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी कलपुर्जा का निर्माण भारत में ही होगा, स्थापित होगा संयुक्त उपक्रम
- भारत को लंबी अवधि के लिए कच्चे तेल, कोयला एवं उर्वरक की आपूर्ति करने को रूस तैयार
- कुडानकुलम के अलावा एक और जगह रूस की तकनीक पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा

- भारत और रूस की सेनाओं के बीच तकनीकी सहयोग पर गठित समिति की बैठक फिर शुरू होगी
- आपसी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गैर-शुल्कीय बाधाएं करेंगे खत्म, यूरोशियाई देशों के साथ एफटीए की संभावना पर होगी बात
- अपनी मुद्राओं में आपसी कारोबार को सेटल करने की होगी व्यवस्था, कृषि एवं खाद्य के क्षेत्र में कारोबार बढ़ाने की तैयारी
- तीन समुद्री मार्गों से आपसी कारोबार को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी
- ओटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट में नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी
- दवा और चिकित्सा उपकरण में अपार संभावनाएं, रूस में खुलेंगे भारतीय कंपनियों के अस्पताल

इसलिए भारत के लिए जरूरी है रूस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस में हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। कूटनीति की दुनिया में संकेत साफ है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की राय कुछ भी हो, भारत रूस के साथ अपने संबंधों को विशेष मानता है। आइये जानते हैं कि रूस भारत के लिए एक अहम और भरोसेमंद देश क्यों बना हुआ है?



शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है रूस

भारत के 60-70 प्रतिशत रक्षा उपकरण रूस और सोवियत मूल के हैं। एसआइपीआरआइ की रिपोर्ट के अनुसार, रूस भारत के लिए अब भी शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, हालांकि भारतीय रक्षा आयात में उसकी हिस्सेदारी 2022 तक घट कर 45 प्रतिशत पर आ गई है। रूस के बाद फ्रांस और अमेरिका क्रमशः 29 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत के लिए बड़े रक्षा आपूर्तिकर्ता हैं। भारत और रूस के बीच कई रक्षा सौदे हुए हैं, जिनके तहत रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हो रही है या होने वाली है। रूस अगले कुछ और दशकों तक रक्षा के क्षेत्र में भारत का अहम सहयोगी बना रहेगा। हालांकि, भारत अपने रक्षा आयात में लगातार विविधता लाने का प्रयास भी कर रहा है।



तेजी से बढ़ रहा है द्विपक्षीय व्यापार

रूस वित्त वर्ष 2021-22 में 13 अरब डालर के साथ भारत का 25 वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत में रूस का कुल निवेश 14 अरब डालर है। इसमें एस्सार आयल के लिए रोजनेपेट द्वारा 13 अरब डालर का निवेश शामिल है। यह सीधा विदेश में रूस का सबसे बड़ा निवेश और भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले भारत और रूस ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 65.70 अरब डालर पर पहुंच गया है। इसकी बड़ी वजह रूस से कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ना है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत रूस से बड़े पैमाने पर सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है।



कूटनीति के मोर्चे पर मिलता रहा है समर्थन

रूस अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार भारत का समर्थन करता रहा है। खास कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मामले पर रूस ने अहम मौकों पर भारत का समर्थन किया है। 2019 में जब अनुच्छेद 370 खत्म किया गया तो रूस ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए भी भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। 2017 के डोकलाम और 2020 के गलवन संकट के समय रूस ने भारत और चीन के बीच तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाई थी।



अमेरिका-चीन फैव्टर

मौजूदा दौर में चीन और रूस के संबंध सबसे बेहतर दौर में हैं। दोनों देश पश्चिमी देशों के प्रभुत्व का विरोध करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में रूस को तेल और गैस के लिए नए ग्राहकों की जरूरत थी, चीन ने रूस की इस जरूरत को काफी हद तक पूरा किया है। वहीं, 2020 में गलवन में सेनाओं के बीच संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। 2014 में क्रीमिया संकट और 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत अमेरिका और रूस के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने को लेकर सतर्क रहा है। अमेरिका रूस को अलग-थलग करने का प्रयास करता रहा है लेकिन भारत ऐसे प्रयासों का समर्थन नहीं करता है।



25 अरब डालर करने का लक्ष्य रखा गया था। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अमेरिका व पश्चिमी देशों के दबाव

को दरकिनार करके रूस से भारी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद की है। इससे भारत को अपेक्षाकृत सस्ती दर पर कच्चा तेल उपलब्ध हुआ

तो युद्ध लड़ रहे रूस को अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जब दुनिया खाद्य, उर्वरक और ईंधन की

कमी महसूस कर रही थी, तब हमने रूस की मदद से अपने किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करने दिया। रूस से तेल और

उर्वरक खरीदने से भारत को महंगाई से लड़ने में मदद मिली है। भारत ने रूस से और ज्यादा उर्वरक खरीदने की मंशा भी जताई है।

FIRST FLIGHT

Historically, nearly half of the first new rocket launches have been failures

Europe's new Ariane 6 rocket set to blast off

Kourou, July 9: After four years of delays, Europe's new Ariane 6 rocket is set to blast off for the first time on Tuesday, carrying with it the continent's hopes of regaining independent access to space.


The inaugural flight of the European Space Agency's (ESA) most powerful rocket yet is scheduled to launch from Europe's spaceport in Kourou, French Guiana at 3pm local time (1800 GMT).

Since the last flight of the rocket's workhorse predecessor, Ariane 5, a year

ago, Europe has been unable to launch satellites or other missions into space without relying on rivals such as Elon Musk's US firm SpaceX.

So many will be nervously watching the launch, hoping it can bring an end to a difficult era for European space efforts.

Historically, nearly half of the first launches of new rockets have ended in failure. That includes Ariane 5, which exploded moments after liftoff in 1996 — but out of its 117 launches over nearly 20 years,

 Teams on the ground would only be able to breathe our first sigh of relief when the first satellites have been released an hour and six minutes after liftoff.

— TONY DOS SANTOS
ESA's Kourou technical manager

only one other flight would fail.

Everyone at the Kourou launch site, which is surrounded by jungle on the South American coast, is hoping history does not

repeat for Ariane 6.

"There is an element of risk because it is a first flight, but we have tried to reduce this as much as possible, so we are confident," said Philippe Baptiste, head of France's CNES space agency.

Tony dos Santos, the ESA's Kourou technical manager, said that teams on the ground would only be able to "breathe our first sigh of relief when the first satellites have been released" an hour and six minutes after liftoff.

From dawn in Kourou,

the vast metal structure housing the rocket will be moved away, unsheathing the 56-metre (183 feet) behemoth. From 10am, its tanks will start to be filled with fuel.

From that point, any physical intervention would force the tanks to be emptied, requiring a 48-hour launch postponement, the ESA's launch base project manager Michel Rizzi said. Concealed in a nearby bunker, more than 200 experts in the launch centre will scrutinise the rocket until liftoff. — AFP



Ariane 6 rocket moves to the launch pad at the Guiana Space Centre, French Guiana, on Tuesday. — AFP

Moscow agrees to repatriate all Indians operating as support staff to Russian military

PIONEER NEWS SERVICE ■
NEW DELHI/MOSCOW

Taking cognisance of India's call to end the recruitment of Indians as support staff to the Russian military, Russia has broadly heeded to this and also agreed to ensure repatriation of those still working in the force, sources said on Tuesday.

It is learnt that Moscow agreed to release the Indians after the issue was brought up by Prime Minister Narendra Modi during an informal meeting with Russian President Vladimir Putin on Monday night. The Russian president hosted a private dinner for the Indian prime minister at the former's residence in Novo-Ogaryovo on the outskirts of Moscow late on Monday evening.

Modi on Monday began a two-day high-profile visit to Russia for the 22nd India-Russia annual summit with President Putin, his first trip since the start of Moscow's invasion of Ukraine.

Last month, Ministry of External Affairs (MEA) said the issue of Indian nationals serving with the Russian Army remains a matter of "utmost concern" and demanded action from Moscow over it.



An announcement on Russia's decision to discharge all the Indians working as support staff to the Russian Army is expected to be made after summit talks between Modi and Putin on Tuesday. Russia has broadly agreed to our request on the issue, the sources said.

On June 11, India said two Indian nationals, who were recruited by the Russian Army, had been killed in the ongoing Russia-Ukraine conflict, which took the number of such deaths to four.

Following the deaths of two Indians, the MEA demanded a "verified stop" to further recruitment of Indian nation-

als by the Russian Army.

In a strongly-worded statement, it said India demanded that there be a "verified stop to any further recruitment of Indian nationals by the Russian Army" and that such activities would not be in "consonance with our partnership."

Earlier in March, 30-year-old Hyderabad resident Mohammed Asfan succumbed to injuries sustained while serving with the Russian troops on the frontlines with Ukraine. In February, Hemal Ashwinbhai Mangua, a 23-year-old resident of Surat, died in a Ukrainian air strike while serving as a "security helper" in the Donetsk region.

